

उडीसा राज्य

बनाम

दाबाकी देवी एंव अन्य

(एवं संबंधित अपीलें)

(ए. के. सरकार, के. सी. दास गुप्ता एवं एन. के. राजगोपाला

अयंगर, जे. जे.)

बिक्री कर- निर्धारण आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण- समय सीमा- उडीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 (उडीसा का 1947 का 14), उपधारा 12,23.

प्रत्यर्थियों का बिक्री कर अधिकारी द्वारा उडीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 के प्रावधानों के तहत बिक्री कर निर्धारण किया गया था जिसने उनके कर योग्य कारोबार से कुछ कटौतियों के दावे को खारिज कर दिया था लेकिन अपील में सहायक कलेक्टर ने दावे को स्वीकार कर लिया। हालाँकि बिक्री कर कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 23(3) के तहत सहायक कलेक्टर के आदेशों का पुनर्विलोकन करते हुए कर योग्य राशि को बढ़ाते हुए कटौतियों की अनुमति प्रदान की। प्रत्यर्थी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत कलेक्टर के आदेशों को निरस्त करवाने के लिए इस आधार पर उडीसा उच्च न्यायालय गए कि उक्त आदेश, जिन तिमाहियों के सम्बन्ध में निर्धारण किया गया था, उनसे छत्तीस माह गुजरने के पश्चात् दिए जाने से अधिनियम के तहत अवैध हैं। उच्च

न्यायालय ने यह विचार लिया कि पुनरीक्षण के आदेश वास्तव में अधिनियम कि धारा 12 की उप-धारा (7) के तहत उस टर्नओवर का पुनर्मूल्यांकन थे जो निर्धारण से बच गया था अथवा कम निर्धारण किया गया तथा वे परिसीमा से वर्जित थे।

निर्णीत किया: (i) उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया यह विचार कि आक्षेपित आदेश वास्तव में उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 की धारा 12(7) के तहत पुनर्मूल्यांकन थे, गलत था।

(ii) (दास गुप्ता और राजगोपाला अयंगर, जे.जे, सरकार जे. के अनुसार). पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेश अधिनियम की धारा 12 व धारा 23 के तहत पारित माने जाने चाहिए और इसलिए धारा 12(6) के दूसरे परन्तुक में बताई गई समय सीमा लागू होती है।

गजो राम बनाम बिहार राज्य, (1955) 7 एस.टी.सी. 248,
अस्वीकृत।

सरकार जे. के अनुसार- (i) धारा 12(7) में बतायी गयी समय सीमा केवल रिटर्न कॉल करने के लिए थी और ना की बचे हुए अथवा कम निर्धारित किये गए टर्नओवर के पुनर्मूल्यांकन के लिए।

(ii) धारा 23 (3) के तहत पुनरीक्षण में पारित किया गया आदेश एक निर्धारण आदेश नहीं है और धारा 12(6) के दूसरे परन्तुक में बताई

गई समय सीमा लागू नहीं होती है।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 454 से 465/1962.

उड़ीसा उच्च न्यायालय द्वारा 1956 की ओ.जे.एस. संख्या 289, 296 एवं 300 में पारित निर्णय/आदेश दिनांकित जुलाई 8, 1958 के विरुद्ध विशेष अनुमति से अपील।

के. एन. राजगोपाल शास्त्री और आर. एन. सचठेय, अपीलकर्ताओं के लिए (सभी अपीलों में)।

संतोष चटर्जी और बी. किशोर, प्रत्यर्थी संख्या 02 के लिए (सी.ए. संख्या 454 से 460/1962 में) और प्रत्यर्थियो (सी.ए. संख्या 461 से 465/1962 में)।

जस्टिस के. सी. दास गुप्ता और जस्टिस एन. राजगोपाला अयंगर का निर्णय जस्टिस दास गुप्ता द्वारा दिया गया, जस्टिस ए. के. सरकार ने असहमतिपूर्ण राय दी।

सरकार, जे. - ये अपीलें यह सवाल उठाती हैं कि क्या उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम, 1947 अधिनियम की धारा 23(3) के तहत मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करने का आदेश देने के लिए समय सीमा निर्धारित करता है। प्रश्न अधिनियम के कुछ प्रावधानों की व्याख्या पर निर्भर करता है जिसका संदर्भ उचित समय पर दिया जाएगा।

तथ्य ये हैं. उत्तरदाताओं का बिक्री कर अधिकारी द्वारा विभिन्न तिमाहियों के संबंध में अधिनियम के तहत बिक्री कर का मूल्यांकन किया गया था। उन्होंनेनेन्हों नेमूल्यांकन के खिलाफ बिक्री कर के सहायक कलेक्टर से अपील की कि बिक्री कर अधिकारी ने उनके कर योग्य टर्नओवर से कुछ कटौती के उनके दावे को गलत तरीके से खारिज कर दिया था। अपीलें स्वीकार कर ली गईं। इसके बाद उड़ीसा उच्च न्यायालय ने एक अन्य मामले में फैसला सुनाया जिससे यह प्रतीत हुआ कि सहायक कलेक्टर ने कटौती की अनुमति देने में गलती की थी। इसके बाद बिक्री कर कलेक्टर ने अधिनियम की धारा 23(3) के तहत कार्य किया, जिसमें यह प्रावधान किया गया था "कलेक्टर, आवेदन पर या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, इस अधिनियम के तहत पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है उसकी सहायता के लिए धारा 3 के तहत नियुक्त व्यक्ति द्वारा" सहायक कलेक्टर के आदेशों को संशोधित कर उनके द्वारा कटौती योग्य कर योग्य टर्नओवर को बढ़ा दिया गया।

उत्तरदाताओं ने कला के तहत उड़ी सा उच्च न्यायालय का रुख किया। संविधान के अनुच्छेद 226 में संशोधन में कलेक्टर के आदेशों को इस आधार पर रद्द करना कि वे अधिनियम के तहत अवैध थे क्योंकिक्यों वे उन तिमाहियों की समाप्ति के छत्ती स महीने से अधिक समय के बाद किए गए थे जिनके संबंध में मूल रूप से मूल्यांकन किया गया था। इस दलील को हाई कोर्ट ने स्वीकार कर लिया. इसलिए ये अपीलें.

उच्च न्यायालय ने माना कि पुनरीक्षण के आदेश अवैध थे क्योंकि वे वास्तव में टर्नओवर का पुनर्मूल्यांकन कर रहे थे जो मूल्यांकन से बच गया था या कम मूल्यांकन किया गया था और अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (7) के तहत ऐसा पुनर्मूल्यांकन नहीं किया जा सकता था। छत्तीस महीने के बाद किसी भी तिमाही के संबंध में। मुझे ऐसा लगता है कि उच्च न्यायालय ने स्वयं को धारा 12 की उप-धारा (7) पर आधारित करके स्पष्ट रूप से गलती की है। उप-धारा का भौतिक भाग इन शर्तों में है: "यदि.... किसी भी अवधि के लिए किसी डीलर का टर्नओवर.... मूल्यांकन से बच गया है या कम मूल्यांकन किया गया है, तो कलेक्टर उस अवधि के अंत के छत्तीस महीने के भीतर किसी भी समय रिटर्न के लिए कॉल कर सकता है।...और आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं..." यहां निर्धारित छत्तीस महीने की समय सीमा केवल रिटर्न के लिए कॉल करने के लिए है। उप-धारा बच गए या कम मूल्यांकन किए गए टर्नओवर के संबंध में पुनर्मूल्यांकन का आदेश देने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं करती है। नतीजतन, यह प्रावधान उन आदेशों को किसी भी तरह से अवैध नहीं बनाता है जिनसे ये अपीलें संबंधित हैं।

फिर हमें इन आदेशों के लिए छत्तीस महीने की समय सीमा निर्दिष्ट करने के लिए अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (6) में दूसरे प्रावधान का उल्लेख किया गया। उपधारा इन शर्तों में है:

"इस धारा के तहत किया गया कोई भी मूल्यांकन इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए शुरू किए गए किसी भी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा:

बशर्ते कि जब कलेक्टर ने इस धारा के तहत मूल्यांकन की गई राशि के अतिरिक्त जुर्माना लगाया हो, तो डीलर के खिलाफ राजस्व या आपराधिक कोई भी आगे की कार्यवाही नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि किसी भी अवधि के संबंध में किसी डीलर से देय कर की राशि का आकलन करने का कोई भी आदेश ऐसी अवधि की समाप्ति से छत्तीस महीने के बाद पारित नहीं किया जाएगा।

मामले में "देय कर की राशि का आकलन करने के आदेश" पर विचार किया गया था। इसलिए सवाल यह है कि परंतुक में "देय कर की राशि का आकलन करने का आदेश" शब्दों का क्या मतलब है? बेशक, संपूर्ण एस. 12 होना चाहिए इन शब्दों के अर्थ तय करने के लिए विचार किया गया और मैं वर्तमान में ऐसा करूंगा। इस बीच हालांकि मैं यह देख सकता हूँ कि हालांकि धारा 12 एक कलेक्टर द्वारा मूल्यांकन की बात करती है, लेकिन इसमें एस के तहत कलेक्टर की सहायता के लिए अधिनियम के तहत नियुक्त अन्य अधिकारियों द्वारा मूल्यांकन शामिल है। धारा 17 में कलेक्टर अपनी शक्तियां ऐसे अधिकारियों को सौंप सकता है, जो उसके अधीनस्थ हों.

अब मैं धारा 12 की ओर मुड़ता हूं। इसमें सात उप-खंड हैं, जिनमें से प्रत्येक उप-धारा 6 को छोड़कर है। एक निर्दिष्ट मामले में मूल्यांकन से संबंधित है। उनमें से प्रत्येक मूल्यांकन के लिए स्पष्ट रूप से एक आदेश प्रदान करता है। पहला उपभाग ऐसे मामले से संबंधित है जहां मूल्यांकन अधिकारी डीलर को सुने बिना या रिटर्न सही होने का सबूत लिए बिना संतुष्ट हो जाता है। दूसरा उप-भाग उस मामले को कवर करता है जहां वह इतना संतुष्ट नहीं है और साक्ष्य सुनने के बाद मूल्यांकन किए जाने का प्रावधान करता है। तीसरी उपधारा उस मामले से संबंधित है जहां डीलर पूर्ववर्ती उपधारा के तहत बुलाए जाने पर उपस्थित होने या साक्ष्य प्रस्तुत करने में विफल रहता है। उप-धारा (4) ऐसे मामले का प्रावधान करती है जब कोई डीलर रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है जो उसे अधिनियम के अनुसार करना आवश्यक है। पांचवीं उपधारा उस मामले से संबंधित है जहां एक डीलर गलत तरीके से पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहता है। छठा उप-खंड पहले निर्धारित किया जा चुका है। अंतिम और सातवां उप-खंड, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, टर्नओवर के मूल्यांकन से संबंधित है जो मूल्यांकन से बच गया था या कम मूल्यांकन किया गया था।

अब मुझे ऐसा नहीं लगता कि धारा 23(3) के तहत दिए गए आदेश को उचित रूप से "देय कर की राशि का आकलन" करने वाला आदेश कहा जा सकता है, जैसा कि अधिनियम में विचार किया गया है।

मैंने पहली बार देखा कि एकमात्र अनुभाग जो कर के मूल्यांकन के लिए स्पष्ट रूप से प्रदान करता है वह एस. 12 है। कोई अन्य अनुभाग मूल्यांकन के आदेश को संदर्भित नहीं करता है। इसका मतलब यह होगा कि एक आदेश देय कर के आकलन का एक आदेश है जब तक कि यह इस धारा के तहत नहीं किया जाता है। तब मैंने पाया कि धारा 23(3) के तहत दिए गए आदेश को मूल्यांकन के आदेश के रूप में वर्णित नहीं किया गया है। वास्तव में यह उपधारा अधिनियम के तहत पारित आदेश को संशोधित करने वाले आदेश से संबंधित है और इसलिए, धारा 12 के तहत किए गए मूल्यांकन के आदेश को संशोधित करती है। यह इस दृष्टिकोण का भी समर्थन करता है कि अधिनियम ऐसे आदेश को मूल्यांकन के आदेश के रूप में नहीं मानता है। . फिर वही निष्कर्ष एस. 23 की उप-धारा (2) द्वारा भी सुझाया गया है जो कहता है कि, "अपीलीय प्राधिकारी किसी भी अपील का निपटारा करने में..... - (ए) पुष्टि कर सकता है, कम कर सकता है, बढ़ा सकता है, या रद्द कर सकता है मूल्यांकन।" जाहिर तौर पर यह नहीं माना जाता है कि कोई अपीलीय प्राधिकारी तब मूल्यांकन करता है जब वह किसी मूल्यांकन की पुष्टि करता है, उसे बढ़ाता है या कम करता है। यदि मूल्यांकन को बढ़ाने वाले अपीलीय आदेश को मूल्यांकन आदेश नहीं माना जाता है, तो न ही संशोधन में पारित समान आदेश पर विचार किया जा सकता है। मेरे विचार में, अधिनियम ऐसे आदेश पर विचार नहीं करता है जो धारा 12 के तहत देय कर की राशि का आकलन करने वाले आदेश के

रूप में नहीं किया गया है।

फिर मुझे लगता है कि जो मैंने ऊपर बताया है उससे यह स्पष्ट है कि धारा 12 की उप-धाराएं (1) से (5) और (7) मूल्यांकन के मूल आदेशों से संबंधित हैं जो अपील में दिए गए आदेशों से अलग हैं। ऐसे मूल आदेशों के संशोधन के माध्यम से या उनकी समीक्षा के माध्यम से। अब उपधारा (6) का पहला भाग और उसका पहला परंतुक स्पष्ट रूप से धारा के तहत दिए गए आदेशों से संबंधित है। इसलिए वे अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों पर लागू नहीं होते हैं। दूसरा प्रावधान जिसके साथ यह मामला जुड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि धारा के तहत मूल्यांकन का कोई स्पष्ट संदर्भ नहीं है, लेकिन यह अजीब होगा यदि वह प्रावधान अपील में या पुनरीक्षण के माध्यम से किए गए मूल्यांकन के आदेशों पर लागू होने का इरादा रखता है, यह मानते हुए कि ऐसे आदेश हो सकते हैं उचित रूप से मूल्यांकन के आदेश कहे जाएंगे। यदि अपील में या पुनरीक्षण के माध्यम से किसी आदेश के लिए सीमा अवधि प्रदान करने का इरादा था तो इसमें शामिल प्रावधान को धारा 12 में नहीं रखा गया होता और न ही आदेश को "कर की राशि का आकलन करने वाले आदेश" के रूप में वर्णित किया गया होता। देय।" ऐसा हो सकता है कि दूसरे परंतुक में निर्दिष्ट समय सीमा उप-धारा (7) के तहत मूल्यांकन के आदेश पर लागू न हो। हालाँकि इससे प्रश्न पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। धारा 12 में एक हालिया संशोधन में स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि दूसरे प्रावधान में समय सीमा उप-

धारा (7) के तहत किसी आदेश पर लागू नहीं होती है।

अंत में, मुझे ऐसा लगता है कि यदि धारा 12(6) में दूसरा परंतुक उस अवधि के अंत से छत्तीस महीने की अवधि तय करता है जिसके भीतर धारा 23(3) के तहत एक आदेश को संशोधित किया जा सकता है उस अवधि के संबंध में मूल्यांकन का आदेश, परिणाम करदाता के लिए इतना विनाशकारी होगा कि इसका इरादा नहीं हो सकता था। इसके बाद यह कलेक्टर के लिए खुला होगा कि वह किसी डीलर द्वारा किए गए मूल्यांकन आदेश के खिलाफ या अपीलीय आदेश के खिलाफ संशोधन के लिए दिए गए आवेदन को छत्तीस महीने का समय बीतने की अनुमति देकर निष्फल कर दे। यह देखना महत्वपूर्ण है कि अधिनियम में कहीं भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें पुनरीक्षण प्राधिकारी को किसी विशेष समयावधि के भीतर उसके समक्ष दायर पुनरीक्षण आवेदन का निपटान करने की आवश्यकता हो और मूल्यांकन का मूल आदेश उस अवधि के भीतर किसी भी समय किया जा सकता है। छत्तीस महीने. इसके अलावा, एक डीलर के पास मूल्यांकन करने में किसी भी देरी के खिलाफ कोई उपाय नहीं है, जब तक कि यह छत्तीस महीने की अवधि के भीतर किया जाता है। इसलिए यह संभव नहीं है कि कई मामलों में किसी डीलर द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दाखिल करने और छत्तीस महीने की अवधि की समाप्ति के बीच ज्यादा समय नहीं बचा हो। यदि दूसरे प्रावधान में निर्दिष्ट समय सीमा धारा 23(3) के तहत एक आदेश पर लागू होती है, तो यह अधिकारियों के लिए

करदाता को धारा 23(3) के तहत आवेदन करने के उसके अधिकार से वंचित करने के लिए खुला होगा। ऐसे परिणाम की ओर ले जाने वाली व्याख्या को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

मामले के इस पहलू को धारा 23(1) द्वारा स्पष्ट किया गया है जो एक डीलर को मूल्यांकन के आदेश की प्राप्ति के तीस दिनों के भीतर अपील दायर करने का अधिकार देता है। जाहिर है, यदि पुनरीक्षण में कोई आदेश एक मूल्यांकन आदेश हो सकता है, तो एक अपीलीय आदेश भी हो सकता है। फिर अपीलीय आदेश छत्तीस महीने की अवधि के भीतर देना होगा। अब मान लीजिए कि छत्तीस महीने की अवधि धारा 23 (1) में उल्लिखित तीस दिनों के भीतर समाप्त हो जाती है, क्योंकि मूल्यांकन का आदेश छत्तीस महीनों के भीतर किसी भी समय किया जा सकता है। ऐसे मामले में जिस व्याख्या के लिए प्रतिवादी डीलर तर्क देते हैं, धारा 23(1) में उल्लिखित तीस दिनों के भीतर अपील दायर करने का अधिकार गायब हो जाएगा, धारा 23(1) और दूसरे के बीच संघर्ष होगा धारा 12(6) का परंतुक से। ऐसे परिणाम की ओर ले जाने वाली व्याख्या सही नहीं हो सकती। संशोधन के लिए आवेदन के मामले में भी यही स्थिति होगी क्योंकि अधिनियम ऐसे आवेदन करने के लिए कोई समय सीमा प्रदान नहीं करता है और इसलिए इसे किसी भी समय करने पर विचार किया जाता है। अधिनियम में एक प्रावधान की व्याख्या जो स्पष्ट रूप से नहीं बल्कि व्यावहारिक रूप से किसी अन्य प्रावधान द्वारा दिए गए संशोधन में आवेदन

करने के अधिकार पर समय सीमा लगाती है, उसकी वैधता संदिग्ध होनी चाहिए। मैं उस व्याख्या को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हूँ क्योंकि यह न तो एकमात्र व्याख्या है और न ही ऐसी व्याख्या है जो इस्तेमाल की गई भाषा द्वारा स्पष्ट रूप से समर्थित है।

यह सच है कि यदि अपील या पुनरीक्षण में कोई आदेश किसी भी समय दिया जा सकता है, तो संबंधित प्राधिकारी के विकल्प पर मामले को डीलर के सिर पर बहुत लंबे समय तक लटकाया जा सकता है। हालाँकि, यह विचार मुझे उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करने के लिए प्रेरित नहीं करता है। जिस विपत्ति और उससे उत्पन्न होने वाली विसंगति का मैंने पहले उल्लेख किया है, वह मुझे उस असुविधा से कहीं अधिक गंभीर लगती है जिससे वह बच जाती है। इसके अलावा, जिस असुविधा की कल्पना की गई है वह मुझे वास्तविक से अधिक काल्पनिक लगती है। यह संभव नहीं है कि अधिकारी जान बूझकर किसी अपील या पुनरीक्षण आवेदन को बिना किसी कारण के लंबित रखेंगे क्योंकि इससे उन्हें कोई फायदा नहीं होगा।

मैं इन कारणों से अपील की अनुमति दूंगा।

दास गुप्ता, जे.- उड़ीसा राज्य द्वारा ये बारह अपीलें बिक्री कर के मूल्यांकन के बारह अलग-अलग आदेशों के संबंध में हैं, जो उड़ीसा बिक्री कर की धारा 23 के तहत संशोधन की अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

बिक्री कर कलेक्टर, उड़ीसा द्वारा किए गए थे। कार्यवाही करना। कई डीलर जो अपील में प्रतिवादी हैं, कला के तहत उड़ीसा उच्च न्यायालय चले गए। संविधान के अनुच्छेद 226 में उचित रिट जारी करने के लिए उड़ीसा राज्य को निर्देश दिया गया है कि वह उन राशियों को एकत्र न करें जिनके बारे में कहा गया था कि उनका अवैध रूप से मूल्यांकन किया गया है। इन कई याचिकाओं को हाईकोर्ट ने मंजूर कर लिया है और कलेक्टर द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेश को रद्द कर दिया है। उड़ीसा राज्य ने इस न्यायालय द्वारा दी गई विशेष अनुमति पर उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ वर्तमान अपील दायर की है।

कलेक्टर द्वारा किए गए सभी आदेश उस अवधि की समाप्ति से 36 महीने के बाद पारित किए गए थे जिसके संबंध में मूल्यांकन किया गया था। कानून का सामान्य प्रश्न जो इन अपीलों में उठता है, वह यह है कि क्या उच्च न्यायालय यह मानने में सही था कि ये आदेश इस आधार पर कानून में खराब हैं कि वे धारा 12 की उप-धारा (6) के दूसरे प्रावधान के प्रावधानों का उल्लंघन करते हैं। उड़ीसा बिक्री कर अधिनियम.

अधिनियम की धारा 4 चार्जिंग धारा है और बिक्री पर कराधान की घटनाओं की घोषणा करती है। धारा 5 कर की दर से संबंधित है। एसएस के प्रावधानों की जांच करना हमारे वर्तमान उद्देश्य के लिए अनावश्यक है। 6 से 10 जो कुछ वस्तुओं को कर मुक्त माल घोषित करने की राज्य

सरकार की शक्ति, कुछ डीलरों को कर से छूट देने, राज्य सरकार की उन बिंदुओं को निर्धारित करने की शक्ति जिन पर माल पर कर लगाया जा सकता है, डीलरों का पंजीकरण, से संबंधित है। पंजीकृत डीलरों की सूची का प्रकाशन एवं डीलरों द्वारा कर संग्रहण के मामले। धारा 11 में कहा गया है कि ऐसे डीलर को कलेक्टर द्वारा निर्धारित तरीके से नोटिस देकर ऐसा करने के लिए कहा जा सकता है और प्रत्येक पंजीकृत डीलर को ऐसे रिटर्न ऐसी तारीखों और ऐसे प्राधिकारी को प्रस्तुत करना होगा जो निर्धारित किया जा सकता है। अधिनियम की धारा 12, जिससे हम मुख्य रूप से चिंतित हैं, कर के निर्धारण के प्रश्न से संबंधित है। इस धारा के पहले पांच उप-खंडों में विधायिका ने अलग-अलग तरीके निर्धारित किए हैं जिनमें कर का आकलन किया जा सकता है। पहले उप-धारा के तहत कलेक्टर संतुष्ट होने पर दिए गए रिटर्न के आधार पर राशि का आकलन करेगा, बिना किसी पंजीकृत डीलर की उपस्थिति या उसके द्वारा किसी सबूत के उत्पादन की आवश्यकता के कि वे सही और पूर्ण हैं। दूसरी और तीसरी उपधारा उस मामले से संबंधित है जहां वह इतना संतुष्ट नहीं है। ऐसे मामलों में कलेक्टर ऐसे साक्ष्यों को सुनने के बाद राशि का आकलन करेगा जो डीलर नोटिस जारी होने के बाद रिटर्न के समर्थन में प्रस्तुत कर सकता है और ऐसे अन्य साक्ष्य जो कलेक्टर को निर्दिष्ट बिंदुओं (उप-धारा 2) पर आवश्यकता हो सकती है; यदि पंजीकृत डीलर जारी किए गए नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है, तो कलेक्टर अपने सर्वोत्तम

निर्णय (उप-धारा 3) के अनुसार कर की राशि का आकलन करेगा, उप-धारा (4) उस मामले से संबंधित है जहां पंजीकृत व्यापारी निर्धारित तिथि तक रिटर्न प्रस्तुत नहीं करता है। ऐसे मामले में भी कलेक्टर पंजीकृत व्यापारी को सुनवाई का उचित अवसर देने के बाद अपने सर्वोत्तम निर्णय के अनुसार कर का निर्धारण करेगा। उप-धारा (5) कलेक्टर द्वारा उस डीलर से देय करों के मूल्यांकन का प्रावधान करती है जिसके बारे में वह संतुष्ट है कि वह किसी भी अवधि के संबंध में अधिनियम के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है और फिर भी पंजीकरण के लिए आवेदन करने में विफल रहा है। इसके बाद उप-धारा (6) आता है जो इस प्रकार चलता है:-

"(6) इस धारा के तहत किया गया कोई भी मूल्यांकन इस अधिनियम के तहत अपराध के लिए शुरू किए गए किसी भी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा:

बशर्ते कि जब कलेक्टर ने इस धारा के तहत निर्धारित राशि के अतिरिक्त जुर्माना लगाया हो, तो आदेश के खिलाफ कोई राजस्व या आपराधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी:

बशर्ते कि किसी भी अवधि के संबंध में किसी डीलर से देय कर की राशि का आकलन करने का कोई भी आदेश ऐसी अवधि की समाप्ति से छत्तीस महीने के बाद पारित नहीं किया जाएगा।

उपधारा (7) में प्रावधान है कि यदि किसी भी कारण से किसी डीलर का टर्नओवर मूल्यांकन से बच गया है या उसका कम मूल्यांकन किया गया है, तो कलेक्टर संबंधित अवधि के अंत के 36 महीने के भीतर रिटर्न मांग सकता है और आगे बढ़ सकता है। उप धाराओं 5 में निर्धारित तरीके से कर की राशि का आकलन करें।

धारा 12 के तहत मूल्यांकन आदेश किए जाने के बाद एक डीलर ऐसे आदेश के खिलाफ निर्धारित प्राधिकारी के पास अपील कर सकता है। यह धारा 23, उप-एस द्वारा प्रदान किया गया है। (1). इसके बाद उन आदेशों से संबंधित प्रावधान आते हैं जिन्हें एक अपीलीय प्राधिकारी पारित कर सकता है और उन संशोधनों के साथ जिन्हें हम निर्धारित करेंगे:

"ऐसे नियमों या प्रक्रिया के अधीन, जो निर्धारित किया जा सकता है, अपीलीय प्राधिकारी, उप-धारा (1) के तहत किसी भी अपील का निपटान करते समय, -

(ए) मूल्यांकन या जुर्माना, यदि कोई हो, या दोनों की पुष्टि करें, कम करें, बढ़ाएं या रद्द करें

(बी) मूल्यांकन या जुर्माना, यदि कोई हो, या दोनों को अलग कर दें और मूल्यांकन प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश दें जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है।

(3) ऐसे नियमों के अधीन, जो निर्धारित किए जा सकते हैं और

लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, कलेक्टर आवेदन पर, या अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, इस अधिनियम या इसके तहत नियमों के तहत पारित किसी भी आदेश को एस के तहत नियुक्त व्यक्ति द्वारा संशोधित कर सकता है। धारा 3 उसकी सहायता करने के लिए, और, जैसा कि ऊपर कहा गया है, राजस्व आयुक्त, उसी तरीके से, कलेक्टर द्वारा पारित किसी भी आदेश को संशोधित कर सकता है।"

जबकि उस अवधि के संबंध में कुछ भी नहीं बताया गया है जिसके भीतर ऐसी पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया जा सकता है; शक्ति को "ऐसे नियमों के अधीन रखा गया है जो निर्धारित किए जा सकते हैं।" अधिनियम की धारा 29 के तहत राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के नियम 54 में कहा गया है कि कलेक्टर अपने स्वयं के प्रस्ताव पर आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनरीक्षण की ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, जबकि राजस्व आयुक्त कर सकता है। कलेक्टर द्वारा किसी भी आदेश के पारित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर पुनरीक्षण की अपनी शक्तियों का प्रयोग करें।

हालाँकि इन सभी मामलों में आक्षेपित आदेश धारा 23(3) के तहत पुनरीक्षण की शक्तियों के कथित प्रयोग में बिक्री कर कलेक्टर द्वारा किए गए थे, कई याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं का दावा है कि आदेश वास्तव में धारा 23(3) के तहत दिए गए थे। अधिनियम की धारा 12(7). उच्च

न्यायालय की राय थी कि धारा 12(7) में धारा 23(3) के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा कि ए गए मूल्यांकन का आदेश भी शामिल है और उस विचार में यह माना गया कि मूल्यांकन के आदेश अंत से छत्तीस महीने से अधिक समय से पारित हुए हैं। विचाराधीन अवधि सीमा द्वारा वर्जित थी।

उड़ीसा राज्य की ओर से पहला तर्क यह है कि उच्च न्यायालय का यह मानना गलत है कि संशोधित प्राधिकरण के मूल्यांकन का आदेश आवश्यक रूप से धारा 12(7) के तहत दिया गया है। धारा 23(3) द्वारा दी गई पुनरीक्षण की शक्ति स्पष्ट रूप से कम मूल्यांकन या छूटे हुए मूल्यांकन के मामले में रिटर्न मांगने के बाद मूल्यांकन करने की शक्ति से एक अलग और अलग शक्ति है। केवल यह तथ्य कि किसी विशेष मामले में पुनरीक्षण प्राधिकारी ने मूल्यांकन के एक नए आदेश द्वारा डीलर को कर के लिए उत्तरदायी बना दिया है जिसके संबंध में उसके बारे में कहा जा सकता है कि उसका कम मूल्यांकन किया गया है या वह मूल्यांकन से बच गया है, दोनों शक्तियों को एक नहीं बनाता है और एक सा। इसलिए हमें उच्च न्यायालय से सहमत होना मुश्किल लगता है कि धारा 12(7) में धारा 23(3) के तहत पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया पुनर्मूल्यांकन भी शामिल है।

हालाँकि यह प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि क्या इस स्थिति को स्वीकार करते हुए कि वर्तमान मामले में कलेक्टर द्वारा दि ए गए आदेश

धारा 12(7) के तहत आदेश नहीं थे, वे अभी भी मूल्यांकन के आदेश थे, जिसकी सीमा धारा 12 के दूसरे प्रावधान द्वारा निर्धारित की गई थी। (6) लागू अपीलकर्ता की ओर से यह आग्रह किया गया है कि इस परंतुक में निर्धारित सीमा केवल धारा 12 के तहत किए गए मूल्यांकन के आदेशों पर लागू होती है और विवा दित आदेश धारा 12 के तहत नहीं बल्कि धारा 23 के तहत किए गए थे और इसलिए इसमें निर्धारित सीमा परन्तुक आक्षेपित आदेशों पर लागू नहीं होता है। सबसे पहले यह ध्यान देने योग्य है कि धारा 12(6) में दूसरे प्रावधान के रूप में जो दिखता है उसका उपधारा के पहले भाग में विधायी प्रावधान से कोई संबंध नहीं है। जो प्रावधान पहले ही निर्धारित किया जा चुका है वह यह है कि धारा 12 के तहत किया गया मूल्यांकन अधिनियम के तहत किसी अपराध के लिए शुरू किए गए किसी भी अभियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगा। पहला प्रावधान निस्संदेह मुख्य प्रावधान से जुड़ा है। हालाँकि, दूसरे प्रावधान में उस मुख्य प्रावधान को बचाने या अपवाद के रूप में कुछ भी नहीं है। इसका किसी अभियोजन के प्रश्न से कोई लेना -देना नहीं है। यदि हम मामले के सार को देखते हैं जैसा कि हमें करना चाहिए, तो यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि कर के मूल्यांकन के आदेश को पारित करने के लिए 36 महीने की सीमा अवधि का प्रावधान वास्तव में अधिनियम का एक स्वतंत्र विधायी प्रावधान है और यद्यपि यह है ड्राफ्ट्समैन द्वारा धारा 12(6) में एक प्रावधान के रूप में डाला गया है, यह मूल रूप से मुख्य प्रावधान का वास्तविक प्रावधान

नहीं है। उस स्वतंत्र विधायी प्रावधान में कहा गया है कि "कर की राशि का आकलन करने का कोई आदेश उस अवधि की समाप्ति से 36 महीने की समाप्ति के बाद पारित नहीं किया जाएगा" जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है। प्रावधान केवल धारा 12 के तहत किए गए मूल्यांकन के आदेशों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसकी भाषा कर की राशि का आकलन करने वाले किसी भी आदेश पर लागू होती है और इसे नियंत्रित करती है, जिसमें स्पष्ट रूप से धारा 12 के अलावा अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत मूल्यांकन शामिल होगा। परिणाम यह है कि भले ही धारा 23 के तहत पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग करते हुए किए गए मूल्यांकन के आदेश को धारा 12 के तहत किया गया आदेश नहीं माना जाए, लेकिन उस अवधि की समाप्ति से 36 महीने की सीमा जिसके लिए मूल्यांकन किया गया है। अभी भी लागू होगा।

श्री शास्त्री ने हालांकि प्रस्तुत किया कि चूंकि विचाराधीन प्रावधान वास्तव में एस. 12(6) में एक परंतुक के रूप में प्रकट होता है, विधायिका का इरादा इसे केवल मूल्यांकन के उन आदेशों पर लागू करना था जिनमें मुख्य प्रावधान जो शब्दों का उपयोग करता है "इस अनुभाग के अंतर्गत किया गया कोई भी मूल्यांकन" संबंधित। चूंकि मुख्य प्रावधान स्पष्ट रूप से केवल धारा 12 के तहत मूल्यांकन के आदेशों से संबंधित है, इसलिए यह तर्क दिया गया कि दूसरे प्रावधान में सीमा की अवधि का उद्देश्य केवल धारा 12 के तहत किए गए मूल्यांकन के आदेशों को नियंत्रित करना था।

हमने पहले ही उन कारणों को निर्धारित कर दिया है जिनके कारण हमें लगता है कि सीमा का यह प्रावधान हालांकि एस. 12 (6) में एक प्रावधान के रूप में दिखाई देता है, वास्तव में एक स्वतंत्र विधायी प्रावधान है, क्योंकि इसकी विषय-वस्तु का इससे कोई लेना-देना नहीं है। एस. 12(6) में मुख्य प्रावधान के साथ, या उप-एस के प्रावधान के साथ। (6) जो इसके पहले है। इसलिए यदि यह वास्तव में एक स्वतंत्र प्रावधान है, जो धारा 12(6) से असंबंधित है, तो हमें इसमें इस निर्माण को आयात करने के लिए कोई तर्क या कारण नहीं दिखता है कि इसका संचालन धारा 12 के तहत मूल्यांकन तक ही सीमित होना चाहिए, स्वयं पढ़ने के लिए या किसी भी उचित निर्माण के तहत यह अधिनियम के तहत किए गए मूल्यांकन के किसी भी आदेश पर लगाई गई एक सीमा प्रतीत होगी, यानी अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत। हालाँकि, तर्क के लिए यह मानते हुए कि यह केवल धारा 12 के तहत मूल्यांकन के आदेशों पर लागू होता है, उस निर्माण से अपीलकर्ता को कोई मदद नहीं मिलती है जब तक कि यह नहीं कहा जा सकता है कि मूल्यांकन के विवादित आदेश धारा 12 के तहत नहीं किए गए थे। हम पाते हैं यह देखना कठिन है कि ऐसा कैसे कहा जा सकता है। यह सच है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि आदेश धारा 23 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के आधार पर किए गए थे। लेकिन धारा 23 स्वयं अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी को अधिनियम के तहत देय कर का आकलन करने की किसी भी स्वतंत्र शक्ति से सुसज्जित नहीं करती है।

धारा 12 के तहत शक्तियां।

धारा 23 की शर्तों की बारीकी से जांच करने से यह स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। आइए सबसे पहले धारा 23(2) के तहत अपीलीय प्राधिकारी की शक्तियों का मामला लें। किसी अपील के निपटारे में वह जो आदेश पारित कर सकता है, उनमें "(बी) मूल्यांकन को रद्द करना और मूल्यांकन प्राधिकारी को ऐसी आगे की जांच के बाद एक नया आदेश पारित करने का निर्देश देना, जैसा कि निर्देशित किया जा सकता है।" श्री शास्त्री ने इस स्थिति पर विवाद नहीं किया कि यदि अपीलीय प्राधिकारी रेखांकित शक्ति का प्रयोग करता है तो "आकलन प्राधिकारी" केवल धारा 12 के तहत नए मूल्यांकन को आगे बढ़ाने के लिए आगे बढ़ सकता है और उस स्थिति में, आगे बढ़ने का उसका अधिकार है। मूल्यांकन धारा 12(6) के दूसरे परंतुक द्वारा निर्धारित 3 वर्ष की सीमा के अधीन होगा। इस प्रकार परिणाम यह होगा कि अपीलीय प्राधिकारी किसी भी समय मूल्यांकन को रद्द करने का आदेश पारित कर सकता है, लेकिन मूल्यांकन प्राधिकारी नए सिरे से मूल्यांकन करने के आदेश को प्रभावी नहीं कर सकता है यदि उस तारीख तक तीन साल की अवधि बीत चुकी हो। इसका वस्तुतः मतलब यह होगा कि यदि अपील के निपटारे की तिथि पर 3 वर्ष की अवधि समाप्त हो गई है या लगभग समाप्त हो गई है, तो अपीलीय प्राधिकारी जिन शक्तियों का प्रयोग कर सकता है, वे सीएल में निर्धारित शक्तियों तक ही सीमित रहेंगी। (ए) एस. 23(2) का, एक परिणाम जिसके बारे में कभी सोचा भी

नहीं गया होगा। दूसरे शब्दों में, यदि अपीलकर्ता द्वारा सुझाए गए निर्माण को स्वीकार कर लिया गया, तो हमारे सामने एक विषम स्थिति होगी कि यदि अपीलीय प्राधिकारी ने मूल्यांकन को रद्द कर दिया और इसे नए आदेशों के लिए भेज दिया, तो कोई नया मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, लेकिन यदि ऐसा करने के बजाय, उन्होंने स्वयं वही पुनर्मूल्यांकन किया, इसमें कोई सीमा नहीं होगी। इसलिए इस तरह के निर्माण पर यह अपीलीय प्राधिकारी के विकल्प पर निर्भर करेगा कि वह यह तय करने के लिए पारित सटीक आदेश पर निर्भर करता है कि कानून द्वारा निर्धारित सीमा अवधि का मूल्यांकन किया जाना चाहिए या नहीं। ही यह अपीलकर्ता के तर्क को खारिज करने के लिए पर्याप्त होना चाहिए कि धारा 23 (2) स्वयं मूल्यांकन को प्रभावित करने की शक्ति का स्रोत था। हमें शायद ही यह जोड़ने की आवश्यकता है कि धारा 23(2) के तहत अपील पर जो लागू होता है वह धारा 23 (3) के तहत संशोधन पर भी लागू होता है, क्योंकि संशोधित प्राधिकारी की शक्तियां और उसके द्वारा पारित किए जाने वाले आदेश किसी भी तरह से भिन्न नहीं होते हैं। अपीलीय प्राधिकारी के तरीके से। इसलिए, हमें यह मानने में कोई झिझक नहीं है कि जब कोई अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी इसे बढ़ाकर नए सिरे से मूल्यांकन कर रहा है, तब भी वह उस शक्ति का प्रयोग कर रहा है जो धारा 12 द्वारा प्रदत्त है, और इसलिए बोलने के लिए, वह कर्तव्य कर रहा है जो एक मूल्यांकनकर्ता करता है। प्राधिकारी ने प्रदर्शन किया होगा या करना चाहिए

था। अपीलीय प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के किसी भी आदेश या जैसा कि वर्तमान अपील में पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किया गया है, को धारा 12 के साथ-साथ धारा 23 के तहत पारित आदेश माना जाना चाहिए। नतीजतन, दूसरे प्रावधान में निर्धारित सीमा की अवधि धारा 12 (6) में शर्तें लागू हो जाएंगी।

लेकिन, श्री शास्त्री कहते हैं, यदि मूल्यांकन के अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों पर लागू होने के लिए 36 महीने की इस सीमा अवधि को रखा जाता है, तो उस विसंगतिपूर्ण स्थिति को देखें। कई मामलों में, वह ठीक ही बताते हैं, ऐसा हो सकता है कि मूल्यांकन का मूल आदेश या तो 36 महीने की अवधि की आखिरी तारीख पर या उससे कुछ समय पहले ही बनाया जाएगा। ऐसे सभी मामलों में 36 महीने की इस अवधि के भीतर कोई अपीलीय आदेश या मूल्यांकन का पुनरीक्षण आदेश संभवतः नहीं दिया जा सकता है। श्री शास्त्री ने हमें यह समझाने की कोशिश की है कि विधायिका द्वारा ऐसे परिणाम की कल्पना नहीं की जा सकती थी। इसलिए, वे कहते हैं, विधायिका को यह मानना चाहिए कि सीमा की यह अवधि केवल मूल्यांकन के मूल आदेशों पर लागू होती है। इस तर्क का स्पष्ट उत्तर यह है कि यदि विधायिका की यही मंशा होती तो ऐसा कहने से आसान कुछ नहीं हो सकता था। इस संबंध में यह बताना भी उचित है कि धारा 12(6) के दूसरे प्रावधान में इस प्रावधान को छोड़कर, अधिनियम में मूल्यांकन के आदेशों की सीमा के संबंध में कोई प्रावधान नहीं है। यदि श्री शास्त्री सही

हैं, तो कानून में स्थिति यह होगी कि एक बार 36 महीने की अवधि के भीतर मूल्यांकन का मूल आदेश हो जाने के बाद अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी किसी भी देरी के बाद मूल्यांकन का आदेश दे सकता है। हमें यह विश्वास करना मुश्किल लगता है कि मूल्यांकन के मूल आदेशों के बारे में सीमा की अवधि निर्धारित करते समय विधायिका मूल्यांकन के अपीलीय या पुनरीक्षण आदेशों के संबंध में ऐसी किसी भी सीमा की अवधि निर्धारित करने से परहेज करेगी। यह सच है कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने स्वयं नियम 54 में आदेश पारित होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि को उस समय के रूप में निर्धारित किया है जिसके भीतर कलेक्टर या राजस्व आयुक्त अपनी प्रेरणा से आदेश को संशोधित कर सकते हैं। लेकिन जिस अवधि के भीतर शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, उसका यह निर्धारण बिल्कुल भी नहीं किया गया होगा या किसी भी समय हटाया जा सकता है। यहां तक कि नियम बनाने वाले प्राधिकारी ने भी कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की है जिसके भीतर मूल्यांकन का अपीलीय आदेश दिया जा सकता है या वह समय जिसके भीतर डीलर द्वारा किसी आवेदन पर पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय कलेक्टर या पुनरीक्षण प्राधिकारी को आदेश पारित करना होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां तक विधायिका का संबंध है, किसी भी पुनरीक्षण आदेश या अपीलीय आदेश के संबंध में परिसीमा के लिए कोई विशेष नियम नहीं बनाया गया है। तथ्य यह है कि अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण

प्राधिकारी द्वारा मूल्यांकन के किसी भी आदेश को पारित करने के लिए विधायिका द्वारा स्वयं कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, यह सोचने का एक और कारण है कि विधायिका का इरादा था कि सीमा की अवधि धारा 12 में निर्धारित है। (6) मूल्यांकन के सभी आदेशों पर लागू होना चाहिए, चाहे वे मूल आदेश हों, हों या अपीलीय आदेश या पुनरीक्षण आदेश हों।

श्री शास्त्री द्वारा बताई गई कठिनाई वास्तव में कुछ मामलों में उत्पन्न हो सकती है। यह उम्मीद करना उचित है कि अधिकांश मामलों में ऐसी कठिनाई उत्पन्न नहीं होगी यदि मूल्यांकन का मूल आदेश शीघ्रता से किया जाए ताकि अपीलीय प्राधिकारी या पुनरीक्षण प्राधिकारी के लिए 36 महीने की इस अवधि के भीतर कार्य करना संभव हो सके। यदि कुछ मामलों में कठिनाई उत्पन्न होती है, तो हमारी राय में, ऊपर उल्लिखित कई विचारों को ध्यान में रखते हुए, यह सोचने का पर्याप्त कारण नहीं है कि विधायिका का इरादा है, ऐसा कहे बिना, कि निर्धारित सीमा की अवधि केवल मूल पर लागू होती है मूल्यांकन के आदेश।

श्री शास्त्री ने हमारा ध्यान गाजो राम बनाम बिहार राज्य, में पटना उच्च न्यायालय के एक फैसले की ओर आकर्षित किया, जहां बिहार बिक्री कर अधिनियम, 1944 की धारा 10(6) में कुछ इसी तरह का प्रावधान लगाया गया था, जहां न्यायालय ने माना कि वहां निर्धारित 24 महीने की

सीमा अवधि केवल मूल्यांकन के मूल आदेशों पर लागू होती है। ऐसा प्रतीत होता है कि विद्वान न्यायाधीश इस तर्क से प्रभावित हुए हैं कि यदि मूल्यांकन के मूल आदेशों और अपीलीय या पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा किए गए मूल्यांकन के आदेशों की सीमा अवधि समान होगी तो बेतुका परिणाम होगा। जिन कारणों का हम पहले ही उल्लेख कर चुके हैं, वह तर्क हमें विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है।

इसलिए हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि मूल्यांकन के आक्षेपित आदेशों को सीमा से रोक दिया गया था, जिस अवधि के लिए कर का मूल्यांकन किया गया था, उसकी समाप्ति के 36 महीने से अधिक समय बाद किया गया था। इसलिए हमारा मानना है कि मूल्यांकन के कई आदेशों को रद्द करने में उच्च न्यायालय सही था।

अपीलें लागत सहित खारिज की जाती हैं। सभी अपीलों के लिए सुनवाई शुल्क का एक सेट होगा।

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार अपीलें लागत सहित खारिज की जाती हैं। सभी अपीलों के लिए सुनवाई शुल्क का एक सेट।

रमन कुमार शर्मा

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 01,

नगर, जिला भरतपुर]

राजस्थान

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राम कुमार शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।